

मुकदमों का विवरण

एच. जे. बेकर और ब्रांस. आई. एन. सी. बनाम

खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम. एम. टी. सी.) (सिविल अपील सं.2437 2010 का) 18 अगस्त, 2023

**[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स**

विचार के लिए विषय:तत्काल अपीलों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जाती है, जिसने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को उस हद तक बरकरार रखते हुए मध्यस्थता पुरस्कार में आंशिक रूप से हस्तक्षेप किया है, जब तक कि पुरस्कार कुछ अवधि के लिए हर्जाना देता है, लेकिन पुरस्कार को शेष अवधि के लिए अलग कर देता है।

मध्यस्थता-हर्जाने का अधिनिर्णय-हस्तक्षेप के साथ-कुछ अवधि के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का अधिनिर्णय-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखा गया, हालांकि, खंड पीठ ने निर्णय को बरकरार रखा, इस हद तक कि पुरस्कार ने कुछ अवधि के लिए हर्जाने की मंजूरी दी, लेकिन इसे शेष अवधि के लिए अलग कर दिया-शुद्धता:

आयोजित किया गया:जहां तक पहली अवधि के संबंध में, निचली अदालतों के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-दूसरी अवधि के संबंध में, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष संरेखण आदेश की एक प्रति पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही दावेदार को व्यवस्था को जारी रखने में अपनी असमर्थता से अवगत कराया-प्रत्यर्थी को जल्द से जल्द उक्त पहलू को संप्रेषित करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया था-इस प्रकार, कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया-इसके अलावा, नुकसान का उपाय एस के अनुसार होना चाहिए।<sup>73</sup>, यानी उल्लंघन की तारीख को माल की बाजार कीमत, अनुबंध मूल्य को कम करना-शेष अवधि के लिए पुरस्कार के संबंध में, डिवीजन बेंच ने माना कि दावेदार के पास शेष राशि के लिए अनुबंध के रूप में सबसे अच्छा सबूत पेश करने में विफलता और नुकसान के प्रमाण के रूप में प्राप्त भुगतान पर्याप्त थे और शिपिंग व्यवस्था के साथ-साथ समय-समय पर पूरे 288 के साथ शिपमेंट के बिल के रूप में।

287

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

विवरण, जिसे बाद की अवधि के लिए किसी भी मुआवजे से वंचित कर दिया गया है, जो कानून के अनुसार है-विवादित निर्णय ने कानून के सही सिद्धांतों को लागू किया, आंशिक रूप से पुरस्कार को अलग करने में-जहां तक ब्याज की दर का संबंध है, समवर्ती निर्णय हुए हैं-अनुबंध अधिनियम, 1873 -एस. 73.[पारस 14-16,18-21]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मेसर्स मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम मेसर्स हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्न [1962] 1 एससीआर 653; अरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1999)

पूरक 2 एस. सी. आर. 621:(1999) 9 एस. सी. सी. 449; वेदांत लिमिटेड बनाम शेनझेन शेडोंग

न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [2018] (12) एस. सी. आर. 829-संदर्भित। फोली बनाम क्लासिक कोच लिमिटेड (1934) 2 के. बी. 1-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.2437

2010.

2001 के एफ. ए. ओ. No.477 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.07.2009 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील No.5286-5287।

रूप:

रमेश सिंह, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम खेतान, सुश्री भारती बदेसरा, श्रीमती बीना गुप्ता, सुश्री रंजना राय गवई, सुश्री वसुधा सेन, विनीत वाधवा, सुश्री दिव्या राय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. एस. एल. पी. (सिविल) संख्या (ओं) में दी गई छुट्टी। 12870-12871 2011 से।

289

एच. जे. बेकर और ब्रॉस. आई. एन. सी. बनाम खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम. एम. टी. सी.) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2. ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय 1 के एक सामान्य फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जो आंशिक रूप से एक मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करता है। प्रत्यर्थी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी गई है-मध्यस्थता में एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (इसके बाद "एम. एम. टी. सी.") इस हद तक कि विवादित निर्णय ने पुरस्कार को रद्द नहीं किया, और मध्यस्थता दावेदार-मेसर्स एच. जे. बेकर एंड ब्रदर्स द्वारा दूसरी अपील आई. एन. सी. (इसके बाद "बेकर") ने उस हद तक किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. एमएमटीसी ने अमेरिकी मूल के सल्फर की खरीद के लिए बेकर के साथ दिनांक 14-01-1986 पर एक समझौता किया। समझौते के संदर्भ में, एम. एम. टी. सी. को वार्षिक आधार पर 60,000 मीट्रिक टन सल्फर (परिवहन सुविधा के लिए +/- 5 प्रतिशत) खरीदना था। यह समझौता आई. डी. 1 से तीन साल के लिए लागू होना था और उसके बाद इसे सालाना हरित आधार पर बढ़ाया जाना था जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा छह महीने के लिखित नोटिस के माध्यम से समाप्त नहीं किया जाता। अनुबंध के तहत, एम. एम. टी. सी. ने 1991 तक सामग्री खरीदी। 20-12-1991 पर, एम. एम. टी. सी. ने बेकर को जनवरी से जून 1992 की अवधि के लिए आपूर्ति-मूल्य के बारे में सूचित किया। चूंकि इस उद्देश्य के लिए कोई पोत नामित नहीं किया गया था, इसलिए 27-01-1992 दिनांकित एक फैक्स द्वारा, बेकर ने एक पोत के नामांकन का अनुरोध किया। आई. डी. 1-1992 को, एम. एम. टी. सी. ने सूचित किया कि वह मई-जून 1992 में 25,000 मीट्रिक टन सल्फर के लिए मार्च 1992 में अपने पोत को नामित करेगा। इसके बाद पोत के नामांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ पत्राचार हुआ।

4. जनवरी-जुलाई 1992 के लिए 50,000 मीट्रिक टन सल्फर की मात्रा एम. एम. टी. सी. द्वारा नहीं उठाई गई थी। इसके बजाय, एम. एम. टी. सी. ने 08-04-1992 पर फैक्स द्वारा बेकर को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा 20-02-1992 पर सल्फर के आयात को रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, वह अनुबंध में शेष मात्रा के खिलाफ किसी भी जहाज को नामित नहीं कर सकता था। बेकर ने जहाज को नामित नहीं करने और सल्फर की शेष मात्रा को उठाने के लिए एमएमटीसी के कारण को स्वीकार नहीं किया। बेकर वांछित मात्रा उठाने पर जोर देते रहे और यह भी कहा कि एम. एम. टी. सी. की निष्क्रियता के कारण, यह भंडारण खर्च भी उठा रहा था। एम. एम. टी. सी. ने अपने 1992 के दिनांकित पत्र में कहा कि खाड़ी से सीधे सल्फर का आयात कम भूमि लागत पर था और बदली हुई स्थिति, अर्थात् केंद्र सरकार द्वारा सल्फर के आयात को डी-कैनैलाइज़ करने के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा से इसका आयात प्रतिस्पर्धी होना बंद हो गया। एम. एम. टी. सी. ने लागत और माल ढुलाई मूल्यों (इसके बाद, "सी एंड एफ मूल्य") के लिए अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि वह बेकर के साथ संबंध जारी रखने के लिए उत्सुक है। उत्तरार्द्ध ने कहा कि डी-कैनैलाइजेशन अनुबंध को प्रभावित नहीं करेगा

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पक्षों और एम. एम. टी. सी. के बीच सहमति मूल्यों पर मात्रा की खरीद करनी थी। अंततः, बेकर ने एम. एम. टी. सी. को पिछले तीन अर्ध-वार्षिक सेमेस्टर यानी जनवरी-जून 1992, जुलाई-दिसंबर 1992 और जनवरी-जून 1993 के लिए हर्जाने का दावा करते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद 19-07-1993 दिनांकित एक और कानूनी नोटिस जारी किया गया। इस कानूनी सूचना द्वारा, बेकर द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया गया था।

5. तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसने दावों पर फैसला सुनाया। अंततः, पुरस्कार 2 के तहत, एम. एम. टी. सी. को दो अलग-अलग अवधियों के लिए बेकर को यू. एस. \$5,10,215 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। एमएमटीसी ने आपत्तियों के माध्यम से इस पुरस्कार को चुनौती दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और पुरस्कार को अदालत का नियम बना दिया गया।<sup>3</sup> एम. एम. टी. सी. ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार दिए जाने के खिलाफ अपील की। अपील पर, खंड पीठ ने विवादित आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, इस हद तक कि पुरस्कार ने जनवरी-जून, 1992 की अवधि के लिए हर्जाना दिया, लेकिन इसे शेष अवधि के लिए अलग कर दिया।

6. 14.01.1986 दिनांकित समझौते के कुछ प्रासंगिक खंड जो इस मामले के लिए सामग्री हैं, नीचे दिए गए हैं:

“खंड 6:- कीमत का निपटान छमाही किया जाएगा और यह कनाडा के उत्पादकों की कीमतों के अनुरूप उनके दीर्घकालिक अनुबंध ग्राहकों के लिए होगा। दोनों पक्ष 15 जनवरी तक जनवरी-जून के दौरान आपूर्ति के लिए और उस वर्ष 15 जुलाई तक जुलाई-दिसंबर के दौरान आपूर्ति के लिए कीमतों का निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि एक सेमेस्टर के दौरान डिलीवरी के लिए कीमत पर कोई समझौता संभव नहीं है, तो उस अवधि के लिए आवंटित मात्रा समाप्त या कम हो सकती है और दोनों पक्ष बाद की अवधि के लिए कीमतों पर बातचीत करने के लिए फिर से मिलेंगे।”

खंड 5:- यह समझौता 1 जनवरी, 1986 से तीन साल के लिए लागू होगा और इसे सालाना हरित आधार पर बढ़ाया जाएगा, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा छह महीने के लिखित नोटिस पर रद्द नहीं किया जाता है।”

7. मध्यस्थता में, बेकर ने तर्क दिया कि एम. एम. टी. सी. ने जनवरी-जून 1992 (1992 की पहली छमाही) की अवधि के दौरान 50,000 मीट्रिक टन सल्फर की खरीद के लिए दिनांकित अनुबंध का उल्लंघन किया था। बेकर ने 1992 की दूसरी छमाही और दो छमाही

सेमेस्टर के दौरान इतनी ही मात्रा में सल्फर उठाने में एम. एम. टी. सी. की विफलता के लिए नुकसान का दावा किया।

2 पुरस्कार दिनांक 07.02.1996

3 1996 के मुकदमा सं. 1038-ए और 1996 के आई. ए. सं. 6093 में दिनांकित 05.09.2001 आदेश द्वारा।

## 291

एच. जे. बेकर और ब्रॉस. आई. एन. सी. बनाम खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम. एम. टी. सी.) [एस. रवींद्र भाट, जे.] 292

1993 और 1994 में से प्रत्येक तीनों सदस्यीय न्यायाधिकरण ने माना कि एम. एम. टी. सी. ने अनुबंध का उल्लंघन किया था और 1992 की पहली छमाही के दौरान 50,000 मीट्रिक टन सल्फर उठाने की इसकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी बरकरार रही। एकल न्यायाधीश ने पाया कि यह याचिका न्यायोचित थी, और जनवरी-जून, 1992 की अवधि के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर और शेष अवधि (जून-दिसंबर 1992) के लिए 300,000 अमेरिकी डॉलर के हर्जाने के पुरस्कार के लिए न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। बाद की अवधि के लिए नुकसान को विवादित निर्णय द्वारा अनुचित माना गया था।

दलों की दलीलें

8. बेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश सिंह और विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीना गुप्ता ने तर्क दिया कि जिस आधार पर विवादित आदेश निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा, यानी, उसने हर्जाने के निर्णय के अंतर्निहित सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा, वह गलत है। यह आग्रह किया गया कि यह परिस्थिति कि कोई पक्ष बाजार नहीं गया था या अपने नुकसान को कम करने का प्रयास नहीं किया था, उसे नुकसान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, एक गलत आधार है। दूसरी ओर, कोई पक्ष बाजार जाता है या नहीं, यह मायने नहीं रखता है और अदालत अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए हर्जाना दे सकती है। रिलायंस को एक पर रखा गया था।

मैसर्स मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम मैसर्स हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्न (इसके बाद, "मुरलीधर चिरंजीलाल") 4 में अदालत का निर्णय कि भले ही कोई पक्ष उल्लंघन की तारीख को बाजार में सामान नहीं खरीदता है, वह उल्लंघन की तारीख को "संबंधित स्थान पर" प्रचलित समान कैनवास के लिए दर के प्रमाण पर हर्जाने का हकदार होगा, अगर वह दर अनुबंधित दर से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे नुकसान हुआ। फोली बनाम क्लासिक कोच लिमिटेड 5 में निर्णय

उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उन पर भी भरोसा किया गया था। 9. बेकर ने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच की यह धारणा कि उल्लंघन की तारीख को माल की कीमत साबित नहीं हुई थी, अनुचित है। अधिवक्ता ने पुरस्कार पर भरोसा किया, यह दिखाने के लिए कि प्रासंगिक अवधि के लिए कीमतें, विचार का हिस्सा थीं, जो अंततः उचित आधार पर बाजार

मूल्य को निर्धारित करने में न्यायाधिकरण के साथ वजन करती थीं, यानी 300,000 अमेरिकी डॉलर। यह आग्रह किया गया था कि मानक "फर्टेकॉन" रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित संविदात्मक वस्तुओं पर अवधि के लिए मूल्य सूचियां, जिन पर दोनों पक्ष सहमत थे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सल्फर की बिक्री की स्थिति को दर्शाती हैं। रिपोर्टों में 1992 के दौरान सल्फर की प्रचलित बाजार कीमतों पर बड़ी संख्या में बिक्री के बारे में बताया गया था। यह तर्क दिया गया था कि नुकसान के माप के संबंध में पुरस्कार में दृष्टिकोण,

4 1962 एस. सी. आर. (1) 653 5 (1934) 2 के. बी. 1

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

साथ ही नुकसान उचित, साक्ष्य आधारित और मनमाना नहीं था। इसे रेखांकित करने के लिए, यह तर्क दिया गया कि बेकर ने विषय अवधि के दौरान संबंधित वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बारे में अपने दावे के समर्थन में कुछ चालान भी रिकॉर्ड में रखे थे। जब तक पुरस्कार में राशि के अनुदान के लिए एक प्रशंसनीय आधार था, जो उसने हर्जाने के लिए किया था, तब तक इसे अलग नहीं किया जा सकता था, जैसा कि विवादित निर्णय ने किया था।

10. यह तर्क दिया गया था कि पहले की अवधि के लिए भी हर्जाने का पुरस्कार, उन वास्तविक मात्राओं पर आधारित था जिन्हें उठाया जाना था। इसलिए, हर्जाना देने का आधार अलग-अलग नहीं था, यह देखते हुए कि बाजार मूल्य का निर्धारण समान था। इन परिस्थितियों में, पुरस्कार पर आपत्तियों को खारिज करने के खिलाफ अपील में, दूसरी अवधि के लिए हर्जाने के पुरस्कार की अस्वीकृति अतार्किक और अन्यायपूर्ण थी। बेकर ने विवादित फैसले का भी समर्थन किया, इस हद तक कि इसने पहली अवधि के लिए पुरस्कार में हर्जाने के अनुदान को बरकरार रखा।

11. एम. एम. टी. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री किरण सूरी ने विवादित फैसले को इस हद तक उचित ठहराया कि उसने फैसले को दरकिनार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने और मुआवजे का पुरस्कार भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद, "अनुबंध अधिनियम") की धारा 73 के अनुसार होना चाहिए।

12. यह भी तर्क दिया गया कि विवादित निर्णय, जिस हद तक यह नुकसान के आधार को बरकरार रखता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपत्तियों को खारिज कर देता है, भी हमले के लिए अतिसंवेदनशील था। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि बेकर को इस बात से अवगत कराया जाए कि अनुबंधित मात्रा डी-कैनैलाइजेशन आदेश के कारण खरीदे गए प्रभाव में नहीं हो सकती है। एम. एम. टी. सी., केंद्र सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के रूप में डी-कैनैलाइजेशन आदेश द्वारा कानून में बाध्य थी और कम से कम उपलब्ध मूल्य पर माल प्राप्त करने के लिए भी बाध्य थी। बेकर ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया जब इसके बारे

में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इन परिस्थितियों में, कम से कम डी-कैनैलाइजेशन आदेश जारी होने की तारीख से जून के अंत तक की पूरी अवधि के लिए हर्जाने का अधिनिर्णय अनुचित था। इसलिए, न्यायालय के निर्णय और निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

13. विद्वान अधिवक्ता ने भी पुरस्कार द्वारा ब्याज देने पर आपत्ति जताई। यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के निर्णयों ने लगातार यह साबित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के संदर्भ में विदेशी मुद्रा में प्रत्यक्ष भुगतान प्रदान करते समय न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण 293 होना चाहिए।

एच. जे. बेकर और ब्रॉस. आई. एन. सी. बनाम खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम. एम. टी. सी.) [एस. रवींद्र भाट, जे.] 294

प्रचलित प्रमुख ऋण दर या एल. आई. बी. ओ. आर. दर के आधार पर। इस मामले में, उन सिद्धांतों को निचली अदालतों और न्यायाधिकरण द्वारा हवा में फेंक दिया गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित निर्णय कानून की त्रुटि का खुलासा करता है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

14. जहाँ तक पहली अवधि का संबंध है, यह अदालत नोटिस करती है कि डिवीजन बेंच ने पुरस्कार में निर्णय और एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। एकल न्यायाधीश ने अरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ 6 में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें पुरस्कारों में हस्तक्षेप की गुंजाइश के बारे में बताया गया था, जो बेहद सीमित है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नुकसान की मात्रा और नुकसान को कम करना तथ्य के प्रश्न हैं जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय निर्णय पर अपील योग्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है। विवादित फैसले में कहा गया कि एम. एम. टी. सी. को इस पहलू पर जोर देने से रोक दिया गया था, क्योंकि नुकसान और शमन के सबूत के इस सवाल पर एकल न्यायाधीश के समक्ष बहस नहीं की गई थी। एमएमटीसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष नुकसान को कम करने की याचिका नहीं उठाई गई थी। चूंकि इस पहलू पर, नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्षों ने निर्णय को लागू किया है, इसलिए इस अदालत के पास निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है।

15. जहाँ तक दूसरे पहलू का संबंध है, (यानी बाद की अवधि के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए देय नुकसान), यह अदालत नोटिस करती है कि हालांकि एम. एम. टी. सी. का दावा है कि केंद्र सरकार ने 29.02.1992 पर नहर बनाने का निर्देश दिया था, यह संचार बेकर को 08.04.1992 पर संबोधित किया गया था। मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायाधिकरण के समक्ष, एम. एम. टी. सी. ने नहर बनाने के आदेश की प्रति पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया। एम. एम. टी. सी. से सबसे कम उम्मीद थी कि बेकर को सूचित किया जाए कि जल्द से जल्द समय पर, यानी मार्च, 1992 के पहले सप्ताह में व्यवस्था को जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने की आवश्यकता है। इसने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना और बेकर के साथ साझा करने

के लिए अप्रैल तक इंतजार किया, कि एक डी-कैनैलाइजेशन आदेश जारी किया गया था। माल न उठाने का कारण आई. डी. 1 पर फिर से डी-कैनैलाइजेशन को बताया गया जब एम. एम. टी. सी. ने बेकर को सूचित किया कि डी-कैनैलाइजेशन आदेश के परिणामस्वरूप बड़ी सल्फर खपत करने वाली इकाइयां खाड़ी देशों से सल्फर का आयात कर रही हैं, जहां उतरने की लागत अमेरिका और अन्य उत्तरी अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से सल्फर की उतरने की लागत की तुलना में बहुत कम थी। एक बार फिर, एम. एम. टी. सी. को कुछ भी नहीं रोका था, कम से कम रिकॉर्ड से, और रोकने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया था।

6 (1999) पूरक 2 एससीआर 621; (1999) 9 एससीसी 449

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

बेकर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए इस पहलू को जल्द से जल्द संप्रेषित करने से। इन कारणों से भी, पिछली अवधि के लिए पुरस्कार में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. अब शेष अवधि, जुलाई-दिसंबर 1992 के लिए पुरस्कार की ओर मुड़ते हुए, इस तथ्य के बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं कि नुकसान का माप अनुबंध अधिनियम की पिछली अंतर्निहित धारा 73 के अनुसार होना चाहिए, यानी उल्लंघन की तारीख पर माल का बाजार मूल्य, अनुबंध मूल्य को कम करना। डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड पर ध्यान देने के बाद कहा कि बेकर ने उस अवधि में शिपिंग समस्या को हल करने से पहले 1992 की दूसरी छमाही के लिए कीमत पर बातचीत करने के लिए अपनी अनिच्छा को स्पष्ट रूप से दिखाया था। इन परिस्थितियों में, कोई बातचीत नहीं हुई और अप्रैल 1992 के बाद कुछ पत्रों को छोड़कर एमएमटीसी से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह दूसरी छमाही के लिए यू. एस. \$3,00,000 की सीमा तक पुरस्कार प्रदान करने का एकमात्र आधार बना। ट्रिब्यूनल ने नोट किया था कि बेकर की ओर से दिए गए कुछ चालानों के अनुसार, सेमेस्टर में बिक्री की कीमतें 37 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लेकर 55 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक दिखाई गई हैं। उस अवधि के लिए, बेकर की ओर से दिए गए कुछ चालानों के संदर्भ में फर्टेकॉन की कीमतें \$58 से \$63 दिखाई गईं। फिर भी, न्यायाधिकरण ने बिक्री मूल्य 49 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया जैसा कि जुलाई से दिसंबर 1992 तक बेकर के नेतृत्व वाले दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। 17. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान बेकर की ओर से किए गए बयानों को डिवीजन बेंच द्वारा ध्यान में रखा गया था। इससे पता चलता है कि तत्कालीन बेकर के उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया था कि कई अनुबंध अलग-अलग दरों पर किए गए थे, जिसमें चिमिक्स डू सेनेगल (सेनेगल) के साथ अलग-अलग दरों पर किए गए थे। अन्य अनुबंधों के बारे में भी बात की गई थी, जो सभी तय की जाने वाली दूरी और विचाराधीन मात्रा के आधार पर अलग-अलग मूल्य सीमा का संकेत देते थे। 18. बयान में यह स्वीकार किया गया था कि पहली अवधि में उठाए जाने वाले माल की मात्रा भी एम. एम.

टी. सी. को जनवरी में आसानी से उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मार्च 1992 में ही उपलब्ध कराई जा सकती थी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, बेकर कम से कम इस बात का सबूत पेश कर सकते थे कि उनके पास रिकॉर्ड में है, जो कि 50,000 मीट्रिक टन सोडियम की बिक्री है। कुछ मामलों में, बेकर ने दावा किया था कि कंपनी अन्य खरीदारों के साथ समझौतों में विश्वसनीय खंडों से बंधी थी। फिर भी, उन अनुबंधों में जहां लागत उपलब्ध कराई गई थी जिनका खुलासा किया जा सकता था और सभी चालान स्वीकार्य थे जैसा कि अनुबंधों की प्रतियां थीं। बेकर द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था जो काफी हद तक उन कुछ चालानों पर निर्भर था जिन्हें उसने 295 निविदा देने के लिए चुना था।

एच. जे. बेकर और ब्रांस. आई. एन. सी. बनाम खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम. एम. टी. सी.) [एस. रवींद्र भाट, जे.] 296

मध्यस्थता कार्यवाहियों और समय-समय पर प्रकाशित फर्टेकॉन मूल्यों में। दिलचस्प बात यह है कि न्यायाधिकरण ने अनुबंध मानक, यानी कनाडाई खरीदार की कीमतों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह अनुबंध का आधार था। यह पुरस्कार किसी भी कारण से रहित है कि बेकर न्यूयॉर्क स्थित आपूर्तिकर्ता था, जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अपनी आपूर्ति प्राप्त की थी, कनाडा की कीमतों के आधार पर विचाराधीन अनुबंधों में आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था, और इसके बजाय, मनमाने ढंग से उस मानक को अस्वीकार कर दिया था।

19. डिवीजन बेंच की राय में, शेष राशि और नुकसान के प्रमाण के रूप में प्राप्त भुगतान के लिए अनुबंधों के रूप में बेकर के पास सबसे अच्छा सबूत पेश करने में विफलता पर्याप्त थी और विचाराधीन शिपिंग व्यवस्था के साथ-साथ समय-समय पर पूरे विवरण के साथ बिल के रूप में शिपमेंट ने इसे बाद की अवधि के लिए किसी भी मुआवजे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि अप्रैल 1992 में यह अच्छी तरह से बताया गया था कि एमएमटीसी द्वारा व्यवस्था को जारी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए डिवीजन बेंच के निर्णय कानून के अनुरूप हैं।

20. यह निर्विवाद है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के अनुसार नुकसान का माप, उस कीमत के बीच का अंतर है जिस पर उल्लंघन की तारीख को बाजार में माल बेचा जाता है, और अनुबंध मूल्य। जैसा कि मुरलीधर चिरंजीलाल में देखा गया है जहाँ वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है

“नुकसान की गणना की जानी चाहिए क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न होंगे। इसका मतलब यह है कि प्रत्यर्थी को समान वस्तुओं के लिए उल्लंघन की तारीख को कानपुर में बाजार दर साबित करनी थी और यह नुकसान की राशि होगी, यदि वह दर उल्लंघन की तारीख को अनुबंध दर के बारे में गई थी।” इसलिए हमारी राय है कि यह उस विशेष प्रकार का मामला नहीं है जिस पर अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में दिखाई देने वाले शब्द “जो पक्षों को पता था, जब उन्होंने अनुबंध किया था, इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है” लागू होते हैं। यह व्यापारियों के बीच

अनुबंध का एक सामान्य मामला है जो खंड में दिखाई देने वाले "जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ" शब्दों द्वारा कवर किया गया है।

उस मामले में, विक्रेता डिलीवरी के स्थान पर, उल्लंघन की तारीख पर, माल की कीमत साबित करने में विफल रहा; अदालत ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। वर्तमान मामले में, इस अदालत का मानना है कि विवादित निर्णय ने आंशिक रूप से पुरस्कार को रद्द करने में कानून के सही सिद्धांतों को लागू किया।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

21. दिलचस्प बात यह है कि जहां तक ब्याज के मुद्दे का संबंध है, बेकर ने इसे किसी भी राहत के अलावा 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान तक लंबित और भविष्य के ब्याज की मांग की थी। एमएमटीसी के जवाब ने इस दावे का खंडन नहीं किया और इस पहलू पर पूरी तरह से चुप रहा। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्न पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, जिसने 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की मंजूरी दी। इस न्यायालय के निर्णय, विशेष रूप से वेदांता लिमिटेड बनाम. शेनझेन

शेडोंग न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद, "वेदांत लिमिटेड") 7

विदेशी मुद्रा में ब्याज के एक समान पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है, और सिफारिश की है कि एल. आई. बी. ओ. आर. दरों और प्रतिशत अंकों में प्रचलित दर को प्रदान किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह अदालत नोट करती है कि ब्याज की दर पर, समवर्ती निर्णय हुए हैं; इसके अलावा, वेदांता लिमिटेड द्वारा नोट किया गया भेद, प्रति स्वयं 'पेटेंट अवैधता' का गठन नहीं करता है, जो पुरस्कार को दूषित करता है। उदाहरण के लिए, यदि पक्ष ब्याज की एक विशेष दर के लिए सहमत होते हैं, तो यह निस्संदेह प्रबल होगा।

22. उपरोक्त कारणों से, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

7 2018 (12) एस. सी. आर. 829